

प्रेषक

विनोद शर्मा,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन,

सेवा में

पुलिस महानिदेशक
पुलिस मुख्यालय, देहरादून,

गृह अनुभाग-8

देहरादून: दिनांक:- 19 मई 2017

विषय:-पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र (पी.टी.सी.) नरेन्द्रनगर के अर्द्धनिर्मित कार्य पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक, पुलिस मुख्यालय के पत्र संख्या: डीजी-दो-526/2002(3) दिनांक 20 सितम्बर 2016 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा शासन के पत्र 990/XX-8/2016-4(47)2013 दिनांक 15.09.2016 के क्रम में पी.टी.सी. नरेन्द्रनगर के आवश्यक अधूरे निर्माण कार्यों को पूर्ण कराये जाने हेतु वर्तमान दरों पर पुनरीक्षित आगणन उपलब्ध कराया गया है। उक्त कार्यों हेतु पूर्व में शासनादेश संख्या: 256/XX-1/24/निर्माण/पु0प्रशि0केन्द्र/12वां वित्त आयोग/(2006-2007)08 दिनांक 04 मार्च 2008 तथा शासनादेश संख्या: 857/XX-1/24/निर्माण/पु0प्र0का0/2006-2007-08 दिनांक 21 अक्टूबर 2009 द्वारा क्रमशः रुपये 500.00 लाख एवं रुपये 950.50 लाख (कुल रुपये 1450.50 लाख मात्र की धनराशि, 12वां वित्त आयोग के अन्तर्गत) पूर्व में अवमुक्त की जा चुकी है। अब उपलब्ध कराये गये रुपये 2025.26 लाख के पुनरीक्षित आगणन की विभागीय टी.ए.सी. वित्त विभाग के परीक्षणोपरान्त आगणन की लागत सिविल कार्यों हेतु रुपये 1751.98 लाख तथा अधिप्राप्ति कार्यों हेतु रुपये 228.68 लाख इस प्रकार योजना की कुल लागत रुपये 1980.67 लाख की पायी गयी है। तत्क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त संस्तुत पुनरीक्षित लागत की कुल धनराशि रुपये 1980.67 लाख की वित्तीय एवं प्रशासनिक अनुमति प्रदान की जाती है तथा निर्माण कार्य को पूर्ण कराये जाने के लिए पूर्व में स्वीकृत धनराशि रुपये 1450.50 लाख को घटाते हुए अवशेष धनराशि रुपये 530.17 लाख के सापेक्ष वर्तमान वित्तीय वर्ष 2017-18 के बजट में उपलब्ध रुपये 83.34 लाख (रुपये तिरासी लाख चौतीस हजार मात्र) की धनराशि आपके निवर्तन पर रखते हुये व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल निम्न शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- कार्य निधारित अवधि में अवश्य पूर्ण कर लिया जाय। इस आगणन के पश्चात कोई भी आगणन पुनरीक्षित नहीं किया जायेगा।

3- वर्तमान परिदृश्य में Energy efficient buildings का निर्माण अतिमहत्वपूर्ण है। अतः

क्रमशः 2

भवनों को विश्व स्तर के मानकों के अनुसार Energy efficient बनाये जाने तथा इस हेतु buildings के सम्बन्ध में विश्व स्तर के मानकों के अनुरूप व्यवस्था की जाय तथा इस सम्बन्ध में Tata Energy Research Institute (TERI) द्वारा जारी Guide line/Representative designs of energy का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

4— सौर ऊर्जा (Solar Energy) के उपयोग का समुचित प्राविधान किया जाय, यथा सोलर गीजर, सोलर कुकर आदि।

5— निर्माण सामग्री Bricks, cement, steel एवं अन्य का Frequency के अनुरूप N.A.B.L. Laboratory से परीक्षण अवश्य कराया लिया जाय।

6— कार्यदायी संस्था कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व का Structural Design सक्षम स्तर से Vet कराया जायेगा साथ ही Reinforcement Steel की मात्रा Bar bending schedule के आधार पर आंकलित किया जाय तथा बचत के सम्बन्ध में प्रशासनिक विभाग को अवगत कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।

7— Electrical Items जैसे Switches, wires, MCB, MCCB, AC आदि Plumbing Items जैसे Bath fittings, Geyser, water tank, pipes आदि Toilet items, wood Items आदि की Market survey कर डी0एस0आर0 दर के अनुरूप गुणवत्ता को ध्यान में रखते हुए प्रशासकीय विभाग के साथ समन्वय स्थापित कर पूर्व में ही कम से कम 3 निर्माता या उनके Authorised Distributor के Quotations प्राप्त कर brand name निर्धारित कर लिया जाय। यदि प्रोक्योरमेंट मदों की लागत रुपये 3.00 लाख से अधिक हो तो कार्यवाही अधिप्राप्ति नियमावली 2008 (यथासंशोधित 2015) के अनुसार की जाय।

8— आगणन में कार्यदायी संस्था द्वारा डी0एस0आर0 की दरें ली गयी हैं एवं उसी के अनुरूप मदें एवं विशिष्टियां भी उल्लिखित हैं। अतः मितव्ययता के दृष्टिकोण से यह अपरिहार्य है कि कार्यदायी संस्था योजना की तकनीकी स्वीकृति प्रदान करते समय उन्ही मदों का आगणन में समायोजन करेंगे जो अपरिहार्य मदें हैं, उदाहरणार्थ—वाटरफूफिंग की मदें अलग से आगणन में ली गयी हैं। यह सही है कि यह मद डी0एस0आर0 में हैं, लेकिन स्थल की आवश्यकता को देखते हुए ऐसा यह अपरिहार्य नहीं है कि उनका प्रयोग भी आवश्यक होगा। अतः तकनीकी स्वीकृति प्राप्त करते समय तकनीकी स्वीकृतकर्ता अधिकारी तकनीकी स्वीकृति प्रदान करने से पूर्व उन मदों का विशेष रूप से ध्यान रखा जाय।

9— वित्त विभाग के शासनादेश संख्या: 284/XXVII(1)/2013 दिनांक 30 मार्च, 2013 में वर्णित व्यवस्था/निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय, ताकि लागत एवं समयवृद्धि(Cost and time over run) से बचा जा सके। यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि

कमश:.....3

कार्यदायी संस्था के साथ वित्त विभाग द्वारा निर्धारित प्रारूप पर M.O.U. हस्ताक्षर कर लिया गया हो।

- 10- एक मुश्त प्राविधानों को कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन गठित कर सक्षम अधिकारी से अनुमोदन प्राप्त कर लिया जाय।
- 11- निर्माण सामग्री को उपयोग में लाने से पूर्व सामग्री का परीक्षण प्रयोगशाला से अवश्य करा लिया जाय तथा उपयुक्त सामग्री ही प्रयोग में लायी जाय।
- 12- मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या-2047 / XIV-219(2006) दिनांक 30 मई 2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कड़ाई से पालन करने का कष्ट करें।
- 13- आगणन में प्राविधानित डिजायन एवं मात्राओं हेतु सम्बन्धित अधिशासी अभियंता एवं अधीक्षण अभियंता पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।
- 14- निर्माण कार्य तथा इस हेतु सामग्री क्रय में Uttarakhand Procurement Rules, 2008 के सुसंगत प्राविधानों का अनुपालन किया जाना सुनिश्चित किया जाय।
- 15- निर्माण कार्य के प्रगति की निरन्तर समीक्षा करते हुये कार्य में शीघ्रता लायी जाय तथा विलम्ब के कारण किसी भी दशा में आगणन पुनरीक्षित नहीं किया जायेगा।
- 16- स्वीकृत धनराशि का व्यय मितव्ययता को दृष्टिगत रखते हुये किया जाय तथा व्यय उन्हीं मदों में किया जाय जिस मद के लिये स्वीकृति प्रदान की गयी है।
- 17- निर्माण कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता के लिये सम्बन्धित निर्माण संस्था उत्तरदायी होगी। कार्य कराते समय वित्तीय हस्तपुस्तिका, बजट मैनुअल एवं तद्विषयक समय-समय पर निर्गत शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- 18- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-10, के अन्तर्गत मुख्य लेखाशीर्षक 4055-पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय, 210-अनुसंधान शिक्षा और प्रशिक्षण, 02-पुलिस प्रशिक्षण कॉलेज की स्थापना के मानक मद 24-वृहद् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।
- 19- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या:- 22 मतदेय /XXVII(5)/2017-18 दिनांक 08 मई, 2017 में प्राप्त उनकी सहमति तथा अलॉटमेंट आई.डी. संख्या: S/1705100159 दिनांक 17 मई, 2017 द्वारा जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय

(विनोद शर्मा)
सचिव

क्रमशः.....4

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं तदनुसार अग्रेत्तर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार, उत्तराखण्ड, ओबराय मोटर्स बिल्डिंग माजरा, देहरादून।
- 2- जिलाधिकारी, टिहरी उत्तराखण्ड।
- 3- निदेशक, कोषागार, 25 लक्ष्मी रोड़, देहरादून।
- 4- वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून/टिहरी, उत्तराखण्ड।
- 5- बजट अधिकारी, बजट निदेशालय, सचिवालय परिसर, देहरादून, उत्तराखण्ड।
- ✓ 6- निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र(एन.आई.सी.) सचिवालय परिसर, देहरादून।
- 7- अधिशासी अभियन्ता, उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लि0 हरिद्वार इकाई।
- 8- वित्त(व्यय नियंत्रक) अनुभाग-5 उत्तराखण्ड शासन।
- 9- नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
- 10- गार्ड फाईल।

आज्ञा से



(मुकेश कुमार राय)
अनु सचिव